दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 26 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 296

महत्वपूर्ण एवं खास

मरने वालों का आंकड़ा 112 पहुंचा, 100 के करीब लापता

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 112 पहुंच गई है और करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। फिलहाल बारिश थमने के कारण जलस्तर कम हो रहा है और राहत अभियानों ने रफ्तार पकड़ी है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और पुणे इत्यादि जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को रायगढ़ जिले के तालिये गांव का दौरा कर राहत और बचाव अभियानों का जायजा लिया। यहां भूस्खलन के कारण कई घर दब गए थे। अब तक मलबे से 42 शव बरामद हो चुके हैं और 39 लोगों की तलाश जारी है। ठाकरे ने कहा कि यह बड़ी घटना है। सरकार पीड़ितों के पुनर्वास के कदम उठाएगी और हर प्रभावित व्यक्ति की मदद की जाएगी।

ट्रक और कार के बीच भिड़ंत, चार लोगों की मौत, एक घायल

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में होशंगाबाद रोड पर चिनार सिटी के सामने रविवार तड़के टाइल्स से भरे एक ट्रक और तेज रफ्तार कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार भोपाल-होशंगाबाद मार्ग पर रविवार तड़के करीब तीन बजे एक तेज रफ्तार कार सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रक से टकराने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। उसके एयरबैग तक फट चुके हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर चारों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवा दिए हैं। मृतकों में ड्राइविंग लाइसेंस से दो लोगों की पहचान अवधपुरी निवासी हिमेश बरैया (30) और 25 साल के आदित्य पांडे के रूप में हुई। बाकी दोनों मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। घायल की पहचान हनी (30) निवासी अवधपुरी के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि पांचों आपस में दोस्त थे और कहीं घूमने जाने के लिए वे कार से निकले थे।

मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आतंकी को मार गिराया, तलाशी अभियान जारी

कुलगाम (आरएनएस)। कुलगाम के मुनंद इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच रविवार सुबह से जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। माना जा रहा है कि अभी और आतंकी सुरक्षाबलों के घेरे में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात सुरक्षाबलों को कुलगाम जिले के मुनंद इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दी थी। सुरक्षाबलों ने सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने अभीतक एक आतंकी को मार गिराया है। माना जा रहा है कि अभी और आतंकी सुरक्षाबलों के घेरे में फंसे हुए हैं।

वर्ली में लिफ्ट हादसे में पांच मजदूरों की मौत, एक घायल

मुंबई (आरएनएस)। वर्ली में स्थित ललित अंबिका नामक निर्माणाधीन बिल्डिंग में शनिवार शाम को अचानक लिफ्ट का तार टूट जाने से हुई हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में घायल लक्ष्मण मंडल (35) का इलाज नायर अस्पताल में जारी है। मुंबई जिले के संरक्षक मंत्री ने इस हादसे की जांच का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस के अनुसार वर्ली स्थित हनुमान गली में निर्माणाधीन ललित अंबिका इमारत की मालवाहक लिफ्ट शनिवार शाम को साढ़े 6 बजे तार टूट जाने से गिर गई। इस हादसे में अविनाश दास (35), भरत मंडल (28), चिन्मय मंडल(33) व दो अन्य मजदूरों की मौत हो गई।

अप्रैल और मई में कोरोना से 1.66 लाख मौतें

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि अप्रैल व मई माह में संक्रमण की वजह से डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मौत के मुहं में समा गये हैं। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना ने लोगों की जान ली।

ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 के बाद से भारत में कोरोना से हुई आधी मौतें सिर्फ दो महीनों यानी अप्रैल और मई 2021 में हुई। ये आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालती है कि दो महीने कितने घातक थे और इसका राज्यों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। भारत में अप्रैल और मई में कोरोना से हुई मौत का 41 प्रतिशत महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से आया। तीन राज्यों ने इस अवधि में सबसे अधिक मौतें दर्ज कीं। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में 14 महीनों में कुल कोविड की मौत का लगभग 60 प्रतिशत अप्रैल और मई में हुआ। सूचना के अधिकारी के तहत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है।

सिर्फ अप्रैल महीने में 1.20 लाख मौतें- एनसीडीसी ने कहा कि अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच कुल 329,065 कोविड मौतों में से, 166,632 अप्रैल और मई 2021 में हुई। मई में 120,770 लोगों की मौत हुई और अप्रैल में 45,882 लोगों की जान गई। जून में, 69,354 कोविड मौतें दर्ज की गई। अप्रैल-मई से पहले, एक महीने के लिए सबसे अधिक मौतें सितंबर 2020 में 33,035 हुई थीं। सितंबर-अक्टूबर को कोरोना की पहली लहर का चरम माना जाता था। उसके बाद फरवरी 2021 में इस महामारी से 2,777 मरीजों की जान गई।

चुनावी राज्यों में बढ़ा मौत का पांच गुना आंकड़ा- देश के पांच राज्यों में 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, चुनाव राज्यों में कोविड की मौत पांच गुना बढ़ गई। आरटीआई से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ गहै।अप्रैल में पश्चिम बंगाल में 921 से मई में 4,162, असम में 177 से 2019 तक, तमिलनाडु में 1,233 से 9,821 और इसी अवधि में केरल में 653 से 3,382 मौतें हुई। डॉ शहीद जमील ने कहा कि इस अवधि के दौरान अधिक मामलों का एक कारण मई में अधिक परीक्षण हो सकता है। मौतों से संकेत मिलता हैं कि राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के संकेतों को नजरअंदाज किया और देर से प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश, जिसने अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच 20,346 मौतों की सूचना दी, वहां मई, 2021 में 8,108 और अप्रैल, 2021 में 3,438 मौतें दर्ज की गईं। पड़ोसी उत्तराखंड में मई में 3,899 मौतों की सूचना दी गई, जो उस महीने उत्तर प्रदेश में हुई कुल मौतों का 48 प्रतिशत है।

भारत ने 43 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कल 43 करोड़ के अहम स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 8 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, 52,72,431 सत्रों के माध्यम से टीकों की कुल 43,31,50,864 डोज लगा दी गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान टीकों की 51,18,210 डोज लगाई गई हैं।

कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महामारी की शुरुआत से अभी तक संक्रमित लोगों में से 3,05,43,138लोग पहले ही कोविड-19 से उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 39,972लोग ठीक हो गए। इस प्रकार ठीक होने की दर 97.36प्रतिशत के स्तर पर है, जिससे लगातार बढ़ोतरी के रुझान का पता चलता है।

पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में दैनिक नए मामले 39,742 दर्ज किए गए।

लगातार 28दिनों से दैनिक नए मामले 50,000 के स्तर से नीचे बने हुए हैं। यह केन्द्र और राज्यों/यूटी द्वारा किए गए निरंतर और सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।

भारत के सक्रिय मामले 4,08,212 के स्तर पर बने हुए हैं और अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 1.30 प्रतिशत है।

देश भर में परीक्षण क्षमता में खासी बढ़ोतरी के साथ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 17,18,756 परीक्षण कराए गए। भारत में अभी तक कुल 45.62 करोड़ (45,62,89,567) परीक्षण हो चुके हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 45.37 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को (निःशुल्क) आपूर्ति करेगी।

भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 45.37 करोड़ से अधिक खुराक (45,37,70,580) सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 11,79,010 खुराक प्रक्रियारत हैं।

आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 42,08,32,021 खुराक की खपत हुई है।

स्कूलों के राजस्व में 20-50 प्रतिशत तक की कमी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय से बंद रहने की वजह से देशभर के ज्यादातर निजी स्कूलों के राजस्व में 20-50 फीसदी की गिरावट आई है, जिससे उनमें से कुछ स्कूलों ने शिक्षकों के वेतन में कटौती की है।

भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा पर काम कर रहे एनजीओ सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन (सीएसएफ) की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट एक अध्ययन पर आधारित है जिसमें 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 1,100 से अधिक अभिभावक, स्कूल प्रशासक और शिक्षक शामिल हुए।

55 प्रतिशत से अधिक स्कूलों ने कहा कि इस अकादमिक वर्ष में नए दाखिलों में भारी कमी आई। गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत शिक्षा का अधिकार कोटा के तहत राज्य सरकार द्वारा चयनित छात्रों को निःशुल्क दाखिला देना होता है। निःशुल्क दाखिले के बदले में राज्य निर्धारित राशि का अग्रिम भुगतान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर स्कूलों के राजस्व में 20-50 फीसदी की कमी आई है, लेकिन खर्च पहले जितना ही बना हुआ है जिसके चलते पहले की तरह स्कूल का संचालन मुश्किल हो गया है। अभिभावकों के नियमित तौर पर फीस न देने के कारण स्कूलों के राजस्व में कमी आई है। शहरी स्कूलों में यह ज्यादा है। 55 प्रतिशत स्कूलों ने सुझाव दिया कि इस अकादमिक वर्ष में नए दाखिलों की संख्या में भारी कमी आई है। कम से कम 77 प्रतिशत स्कूलों ने कहा कि वे कोविड-19 के दौरान स्कूलों की वित्तीय मदद के लिए कर्ज नहीं लेना चाहते और केवल तीन प्रतिशत ने ही सफलतापूर्वक कर्ज लिया, जबकि पांच फीसदी अपने कर्ज को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के कम से कम 55 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन में कटौती हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम फीस वाले स्कूलों ने 65 प्रतिशत शिक्षकों का वेतन रोक रखा है, जबकि अधिक फीस वाले स्कूलों ने 37 प्रतिशत शिक्षकों का वेतन रोक रखा है। कम से कम 54 प्रतिशत शिक्षकों की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, जबकि 30 प्रतिशत शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वहीं, कम से कम 70 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि स्कूल की फीस पहले जैसी ही है और केवल 50 प्रतिशत अभिभावक ही फीस दे रहे हैं जो स्कूलों के राजस्व में कमी का संकेत है।

सेना, नौसेना, वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ में बाढ़ प्रभावितों को बचाने के काम में जुटी

नईदिल्ली (आरएनएस)। सेना के तीनों अंगों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में नागरिक प्रशासन और राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली जिलों के प्रशासन के साथ करीबी समन्वय बना कर काम करते हुए, भारतीय सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में इन्फैंट्री, इंजीनियर्स, संचार, रिकवरी और मेडिकल टीमों सहित अपनी टास्कफोर्सेज़ को तैनात किया है । इन टीमों ने चिपलून, शिरोल, हाटकंगल, पलुस और मिराज क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किया और कीमती जानें बचाई।

कर्नाटक में भारतीय नौसेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए नौसेना के गोताखोरों, रबर जेमिनी नावों, लाइफ जैकेट और चिकित्सा उपकरणों के साथ सात बेहतर ढंग से सुसज्जित बाढ़ राहत दलों की तैनाती की। टीमों ने कादरा बांध के पास सिंगुड्डा और भैरे गांवों से 165 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला, जबकि 70 लोगों को कैगा के निचले इलाकों से निकाला गया।

नौसेना के सीकिंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और भारतीय वायु सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टरों ने अनेक उड़ानें भरीं और जल स्तर में अचानक और तेज वृद्धि के कारण फंसे लोगों की जान बचाई। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया ताकि वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का आकलन कर सकें और बचाव और राहत कार्यों की योजना बना सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के लगभग 400 कर्मियों को भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा भुवनेश्वर, कोलकाता और वडोदरा से पुणे, कोल्हापुर और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और गोवा 40 टन बचाव उपकरणों के साथ एयरलिफ्ट किया।

किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आकर 9 पर्यटकों की मौत, 3 घायल

» बटसेरी का बैली ब्रिज भी टूटा

किन्नौर,25 जुलाई (आरएनएस)। हिमाचल के किन्नौर में बड़े हादसे की खबर है। यहां भूस्खलन की चपेट में आने के कारण 9 पर्यटकों की मौत जबकि तीन घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी पर पत्थर गिरने से नौ की मौत हो गई जबकि तीन घायल हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे चट्टान से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे है। इस वीडियो को देखकर हर कोई सहम गया और वहां चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। पहाड़ से भूस्खलन सहित चट्टानें गिरने से बास्पा नदी पर बना करोड़ों का पुल टूट गया है और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाड़ियों पर पत्थर गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है वह दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और जयपुर के रहने वाले थे, जो हिमाचल में घूमने के लिए आए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस जासूसी कांड की जांच

» सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की जासूसी की रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अधिवक्ता एम एल शर्मा ने याचिका दायर कर मांग

की थी कि न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच कराई जाए।

दरअसल, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों सहित लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। इससे पगले अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य ब्रिटास ने रविवार को एक बयान में कहा कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने संबंधी परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसलिए, इस संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए थे। लेकिन सरकार ने स्पाईवेयर द्वारा जासूसी से न तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया है। पेगासस विवाद पर सरकार ने कहा था कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है तब अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा था कि संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले रिपोर्ट का आना संयोग नहीं है। उन्होंने कहा था, अतीत में व्हाट्सऐप पर पेगासस के इस्तेमाल करने का दावा सामने आया। इन खबरों का तथ्यात्मक आधार नहीं है और सभी पक्षों ने इससे इनकार किया है। हालांकि मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ने दावा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ रसूखदार लोगों सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर, हो सकता है कि हैक किए गए हों।